अब कृष्णा कॉलोनी की झुग्गियां तोड़ दीं! पहले आवास समस्या पैदा करती है, फ़िर झुग्गियां उजाड़ती है सरकार

फ़रीदाबाद (म.मो.) नीलम व बाटा पुलों के बीच रेलवे लाइन के किनारे बसी कृष्णा कॉलोनी की सैंकड़ों झुग्गियां एक झटके में उजाड़ दी गयीं। थोड़ा सा विरोध किया तो पुलिस ने दिखाई लाठी व बंदूक।

यह ठीक है कि उक्त कॉलोनी गत 40 वर्षों से रेलवे की ज़मीन पर अवैध रूप से बसी थी। अब रेलवे को इस ज़मीन की जरूरत है तो उसे झुग्गियां हटाने का पूरा हक है। परन्तु उनका हक कहां गया जो बरसों से इस औद्योगिक नगरी में मेहनत मज़दूरी करके यहां की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं?

भारत सरकार की उद्योग नीति के अनुसार प्रत्येक उद्योगपति के लिये यह अनिवार्य था कि वह कारखाना खड़ा करने के साथ-साथ अपने श्रमिकों के रहने हेतु कॉलोनी भी बनाये। इसके लिये सरकार ने कारखानेदारों को बड़े-बड़े आवासीय प्लॉट भी दिये थे। शहर के एनआईटी एक व दो नम्बर में ब्राउन बावेरी ने अपने सैंकड़ों कर्मचारियों के लिये कॉलोनी बनाई थी लेकिन भ्रष्ट सरकारों ने उन आवासीय कॉलोनियों को व्यापारिक स्थलों में बदल दिया। ऐसे ही बाटा, हार्डवेयर व अन्य कम्पनियों ने कर दिया। एस्कॉर्टस कम्पनी ने तो सेक्टर 13 के आवासीय भूखंड पर एक कारखाना ही खड़ा कर दिया।

बिना लाभ-हानि के तमाम नागरिकों को आवास उपलब्ध कराने के नाम पर बनाया गया एच यू डी ए (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) खुली लूट व रिश्वतखोरी का पर्याप्त बन कर रह गया है। जहां 80 प्रतिशत आबादी को 36 गज़, 60 या 100 गज़ के प्लॉट चाहिये, वहां हूडा अपने सेक्टरों में 80 प्रतिशत प्लॉट 250 वर्ग गज़ से लेकर 1000 वर्ग गज़ के बनाता है और वे भी चौगुणे-छहगुणे मुनाफ़े पर बेचता है। वह बात अलग है कि इस मुनाफ़े का एक बड़ा भाग भ्रष्टाचारी अधिकारी व नेता निगल जाते हैं।

ऐसे में अनाधिकृत कॉलोनियों के दबंग एवं राजनेता भी ग़रीब जनता को खूब बेवकूफ़ बना कर ठगते व लूटते हैं। इन सब मजबूरियों के चलते ग़रीब मज़दूर गंदे नालों, रेलवे लाइन के किनारे व ऐसे ही अन्य स्थानों पर सूअरबाड़ों जैसे अपने घरौंदे बना लेते हैं। धीरे-धीरे ये घरौंदे बस्तियों का रूप धारण कर लेते हैं। फ़िर यहां नेताओं का आवागमन होता है। राशन कार्ड व वोटर कार्ड बनते हैं। इन बस्तियों को टूटने से बचाने या जरूरत पड़े तो तोड़ने की धमकी देकर इन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये मज़दूर भी बस इसी बात से संतुष्ट रहते हैं कि उनके सूअरबाड़े बने रहें, उन्हें उजाड़ा न जाय।

उक्त कृष्णा नगर में तोड़-फ़ोड़ के समय ऐसे ही कुछ लोग़ों ने स्थानीय विधायक एवं मंत्री विपुल गोयल को फ़ोन लगाया तो उनके भतीजे ने तुरंत तोड़-फ़ोड़ को रुकवाने का आश्वासन दे दिया तुरंत ही उपायुक्त को फ़ोन लगाने का नाटक भी किया गया। इस बीच रेलवे को अपनी जितनी जगह खाली करानी थी, वह खाली हो चुकी थी। मन्त्री जी का अवश्वासन भी रह गया और वोट बैंक भी कायम रह गया। श्रमिक वर्ग की समझ जब तक इस तरह के आश्वासनों व धोखों से आगे नहीं बढेगी, वे यूं ही उजड़ते व पिसते रहेंगे।

महाराणा प्रताप दिवस पर भीम आर्मी के अध्यक्ष के भाई की गोली मारकर हत्या

जनज्वार, सहारनपुर भीम आर्मी के सहारनपुर जिलाध्यक्ष कमल वालिया के भाई सचिन वालिया की आज गोली मारकर हत्या कर दी गयी। सचिन की गोली से उस समय हत्या हुई जब वह रामनगर गांव से सहारपुर शहर की ओर आ रहे महाराणा प्रताप जुलूस के बगल से वह गुजर रहे थे।

भीम आर्मी के संघर्षों को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजी एसआर दारापुरी ने बताया कि पुलिस का कहना है वह प्रोसेशन के बगल में गिर गया, जबकि परिजनों का कहना है कि उसकी हत्या हुई है।

जेल में बंद भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आज पांचवें दिन भूख हड़ताल पर

सहारनपुर भीम आर्मी के सचिन वालिया के साथी प्रदीप नारवाल के अनुसार सचिन की राजपूतों ने गोली मारके हत्या कर दी है। सचिन वालिया सहारनपुर भीम आर्मी अध्यक्ष कमल वालिया के भाई हैं। अभी अभी सहारनपुर के साथी ने बताया की आज महाराणा प्रताप शोभा यात्रा निकालते वक्त राजपूतो ने गोली मारी। अभी कुछ दिन पहले कमल वालिया जेल से छूटे हैं।

सचिन की मौत के बाद मामले की जांच कर रही पुलिस का कहना है कि अभी सचिन वालिया का पोस्टमार्टम हो रहा है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कहा जा सकता है कि मौत का कारण क्या है। यानी उसे गोली मारी गई है या मौत की वजह कुछ और है।

हत्या के विरोध में सहारनपुर जिला अस्पताल के बाहर सचिन के भाई और परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। परिजनों

का आरोप है कि सचिन को प्रशासन ने मरवाया है। इसीलिए परिजन सचिन के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने का भी विरोध किया, जिसके बाद मौजूदा पुलिस प्रशासन को बल प्रयोग भी करना पड़ा।

हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि महाराणा प्रताप जयंती को देखते हुए हमने अलर्ट जारी किया था और महाराणा प्रताप भवन पर 800 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। प्रशासन का कहना है कि हमने 200 लोगों को जयंती मनाने की सशर्त अनुमति दी थी, जबकि भीम आर्मी ने जयंती न मनाने की चेतावनी भी दी थी। शायद यही कारण रहा हो कि हत्या को अंजाम दे दिया गया हो।

सचिन वालिया की हत्या पर रिहाई मंच के महासचिव राजीव यादव ने दुख दु:ख प्रकट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में सामंती तत्वों के मनोबल चरम पर हैं, क्योंकि सामन्ती ताकतों के सरगना खुद मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ पहले हिन्दू युवा वाहिनी के सामन्ती गुंडों के सरगना थे और अब मुख्यमंत्री के तौर पर राजपूत अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। भीम आर्मी के नेताओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर रासुका लगाकर जेल बंद किया जाना एक रणनीति है, ताकि नाइंसाफी के खिलाफ कोई बोले नहीं, दूसरी तरफ सहारनपुर समते पूरे सूबे में शासन-प्रशासन राजपूत अपराधियों न सिर्फ बचा रहा बल्कि उनके सहयोगी की भूमिका निभा रहा है।

विदेश भ्रमण तमाशे पर मुख्यमंत्री खट्टर!

दिल्ली (म.मो.) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हुए अपनी औकात के अनुसार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी गत सप्ताह 10 दिन के विदेश भ्रमण पर निकल गये हैं। पहले चरण में वे इस्रायल पहुंच गये। वहां वे खेती, बागवानी व सिंचाई से सम्बन्धित तकनीकी जानकारियां तो लेंगे ही साथ में आन्तरिक सुरक्षा के बारे में भी कुछ सीखने समझने का प्रयास करें।

साल डेढ साल बाद खट्टर जी व उनकी भाजपा हरियाणा के तमाम कार्यभार से मुक्त होने वाले हैं। तो क्या उसके बाद संघ प्रचारक का दायित्व निभाने की बजाय वे खेती, किसानी एवं बागबानी तथा डेयरी चलाने का धंधा अपनाने वाले हैं? यदि यही काम करना है तो करनाल ज़िले के घरोंडा सहित देश भर में इस्रायल ने अनेकों पॉली हाउस फ़ार्म बना कर किसानों को प्रशिक्षण देने का काम शुरु कर रखा है। हिसार स्थित कृषि विश्व विद्यालय तथा करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में भी इस्रायली सहयोग से काफ़ी काम हो रहा है। खट्टर को यदि सैर सपाटे की बजाय वास्तव में ही कुछ सीखना था तो इन्हीं स्थानों पर कुछ दिन रहकर कुछ सीख लेते। शायद कुछ ज़्यादा ही सीख पाते और वह भी बिना सरकारी खर्चे के।

परन्तु सीखना किसे है, यह तो एक बहाना है। इसी तरह का एक बहाना बना कर खट्टर जी विलायत यात्रा करेंगे। वहां के लोग़ों से वे भारत में पूंजी निवेश करवायेंगे। इससे पहले वे सिंगापुर आदि देशों से भी पूंजी लाने के नाम पर भ्रमण कर चुके हैं। न वहां से कोई चवन्नी आई न ही विलायत से कुछ आना है। जाहिर है इन देशों के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं जो बहकावे में आकर अपनी पूंजी यहां निवेश कर के अपना माथा पीटें। वहां बैठें पूंजीपतियों एवं उद्योगपतियों को वहीं बैठे बिठाये वह सब कुछ दिख रहा है जो इस देश में हो रहा है। उन्हें दिख रहा है कि कैसे जीएसटी की मार व भ्रष्टाचार से यहां का व्यापारी एवं उद्योगपति बेज़ार है। सरकार की ढुलमुल नीतियों के चलते वे कोई स्थाई योजना एवं कार्यनीति नहीं बना पा रहे।

हां जिन उद्योगपतियों ने भारत में निवेश करना ही होता है वे अम्बानी, अडानी, टाटा, बिरला आदि बड़े उद्योगपतियों के साथ मिल कर निवेश करते भी हैं। उन्हें किसी खट्टर या मोदी के निमन्त्रण अथवा प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं रहती। वे अपना नफ़ा-नुक्सान, भला-बुरा आंकने में कहीं ज्यादा सक्षम एवं समझदार हैं। रही बात भ्रमण की तो वह खट्टर को जरूर कर लेना चाहिये क्योंकि जिंदगी में ऐसा फोकट का माल फ़िर तो कभी हाथ लगने वाला नहीं। डेढ दो साल बाद तो फ़िर डांडे ढोने ही हैं।

बी.के. अस्पताल में लूट के एक से बढ कर एक तरीके

फ़रीदाबाद (म.मो.) नागरिकों की मुफ़्त चिकित्सा सेवा का दावा करने वाली खट्टर सरकार का बीके अस्पताल अपने यहां आने वाले मरीज़ों को लूटने व ठगने के एक से बढ कर एक तरीके अपना रहा है। डॉक्टरों की कमी के चलते दुख पाये मरीज़ डॉक्टरों से सेटिंग करके उन्हें प्राइवेटली मिलने का जुगाड़ लगाते हैं। अल्ट्रासाऊंड, एक्सरे, व प्रयोगशाला की अपर्याप्त सुविधाओं के चलते मरीज़ों को बाहर से जांच कराने को कहा जाता है। प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट तो कभी भरोसेमंद होती ही नहीं इसलिये बाहर से जांच कराना जरूरी बताया जाता है। अस्पताल के बाहर बैठे जांचकर्ता मरीज़ों से मोटी फ़ीस वसूल कर उसमें से मोटा कमीशन रैफ़र करने वाले डॉक्टरों को देते हैं।

ऑपरेशन थियेटर (ओटी) में चाहे जनरल सर्जरी हो या हड्डियों की या प्रसूति से सम्बन्धित कोई भी ऑपरेशन, मरीज के तीमारदारों को बाहर से सामान खरीद कर लाने के लिये एक लम्बी लिस्ट थमा दी जाती है। इसमें सर्जिकल सामान के अलावा दवायें व पट्टियां और रुई तक भी शामिल होती है। यानी कि और सामान तो छोड़ो रुई व पट्टियां तक भी अस्पताल स्टॉक में नहीं दिखाई जा रही। मजे की बात तो यह है कि यह सारा सामान मरीज की जरूरत से करीब दोगुणा मंगा लिया जाता है। जाहिर है बचा हुआ सामान वापस उसी दुकान पर शाम तक वापस पहुंच जाता है।

खास बात यह भी है कि मरीज़ों को सामान खरीदने के लिये एक दुकान विशेष का पता दिया जाता है। वह दुकानदार पहले तो दाम ही बढा-चढा कर वसूलता है, फ़िर शाम को वापस आये सामान को दोबारा बेच देता है।

इस सारे सौदे में डॉक्टर सहित उसका मातहत स्टाफ़ भी शामिल रहता है। ऐसा नहीं है कि यह धंधा कोई चोरी-छिपे चल रहा हो, यह बिल्कुल चौड़े में चल रहा है। जाहिर है ऐसा तभी संभव हो सकता है जब इसको रोकने वाले अधिकारी सीएमओ गुलशन अरोड़ा व उनकी यहां तैनाती बनाये रखने वाले राजनेताओं का संरक्षण उपलब्ध हो।

लालकिले को निजी हाथों में सौंपने वाली सरकार ने हेडगेवार की समाधि को दिया पर्यटन स्थल का दर्जा

नई दिल्ली/नागपुर। केंद्र की मोदी सरकार जब देश की राष्ट्रीय धरोहरों लाल किला और ताजमहल को निजी घरानों के हाथ में बेचने का फैसला ले रही थी उसी समय नागपुर में आरएसएस के संस्थापक केशवराव बलिराम हेडगेवार के समाधि स्थल को पर्यटल स्थल का दर्जा दिया जा रहा था। एक तरफ सरकार पैसे की कमी का रोना रोकर राष्ट्रीय धरोहरों की नीलामी का अपराध कर रही है दूसरी तरफ ऐसे शख्स की समाधि के रखरखाव का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी ले रही है जिसकी राष्ट्रीय और सामाजिक आंदोलन में भूमिका नगण्य है। और जो हिंदुत्व के नाम पर देश में नफरत और घृणा फैलाने के लिए जाना जाता है।

नागपुर के जिलाधिकारी ने 17 अप्रैल को इस आशय की अधिसूचना जारी की। जिसके तहत उसने कहा है कि रेशमीबाग स्थित हेडगेवार स्मृति मंदिर परिसर को क वर्ग के पर्यटन स्थल का दर्जा दिया जाता है। आपको बता दें केशराव बलिराम हेडगेवार आरएसएस के संस्थापक थे और उन्होंने ही 1925 में इस संगठन की स्थापना की थी। हर साल दशहरा के दिन संगठन अपना स्थापना दिवस मनाता है।

लेकिन इस फैसले के साथ ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। और जिले के कई सामाजिक संगठन और व्यक्ति आगे आए हैं। इस सिलसिले में इन लोगों ने जिले के आला अधिकारियों को ज्ञापन दिया है। उनका कहना है कि हेडगेवार की राष्ट्रीय आंदोलन में कोई भूमिका नहीं थी और न ही आरएसएस ने समाज में ऐसी कोई भूमिका निभाई है जिसके लिए उसके संस्थापक को सरकार ऐसा सम्मान दे।

सात मई को नागपुर के कमिश्नर को सौंपे गए एक ज्ञापन में सामाजिक कार्यकर्ता मोहनिश जीवनलाल जबलपुरे ने इस अधिसूचना को निरस्त करने मांग की है। उन्होंने इस फैसले को लेने वाले पूर्व जिलाधिकारी सचिन कुर्वे को संघ परिवार का सदस्य बताया है। साथ ही आरोप लगाया है कि संघ और बीजेपी से उनके नजदीकी रिश्ते रहे हैं।

उन्होंने अपने ज्ञापन में कहा है कि अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने वाले बहादुरशाह जफर और हिंदुस्तान की राजधानी में स्थित लाल किला ये दोनों हमारे लिए शौर्य और सम्मान के प्रतीक रहे हैं। और आजादी के बाद लाल किला हमारी स्वतंत्रता की निशानी और शान रहा है। लेकिन बीजेपी सरकार ने उसे निजी हाथों में सौंप दिया। इसके पीछे उसका मकसद लाल किले के ऐतिहासिक महत्व को कम करना है। और फिर स्वतंत्रता आंदोलन में जिसका रत्ती भर योगदान नहीं रहा है उसके स्मृति मंदिर को पर्यटन स्थल का दर्जा देना आने वाली पीढ़ियों को गलत इतिहास बताने की कोशिश का हिस्सा है। उनका कहना है कि इस काम को इसी नजरिये से अंजाम दिया गया है।

ज्ञापन में कहा गया है कि हेडगेवार ने देश में जातिवाद फैलाने का काम किया और हिंदुत्व के नाम पर देश और समाज में सांप्रदायिक घृणा और नफरत का बीज बोया था। ये विचारधारा न केवल हिंदुओं को बांटती है बल्कि मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध सभी धर्मों का भी विरोध करती है।

उनका कहना है कि स्मृतिमंदिर को संचालित करने का काम आरएसएस द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट करता है। और इसका इस्तेमाल संघ अपने निजी हितों के लिए करता है। ऐसे में उसके सरकारी खर्चे पर रखरखाव का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। ये संगठन देश के संविधान के सर्वधर्म समभाव के विचारों के खिलाफ काम करता है लिहाजा उसके मुखिया की समाधि को पर्यटन स्थल घोषित करना संवैधानिक मान्यताओं के भी खिलाफ है। लिहाजा प्रशासन पर्यटनस्थल घोषित करने की अधिसूचना को तत्काल रद्द करे।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06